आतंकवाद पर जीरो ट्रोलेंस अपनाए दुनिया

मास्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ सम्मेलन में दो टूक कहा - आतंक पर लीपापोती नहीं

नई दिल्ली 18 नवम्बर. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आतंकवाद को गंभीर खतरा बताते हुए दुनिया से इसे कतई बर्दाश्त नहीं करने का आह्वान किया है और कहा है कि आतंकवाद को लेकर कोई लीपापोती नहीं की जा सकती.

डॉ. जयशंकर ने बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की कार्य प्रणाली में सुधारों की भी पुरजोर वकालत की है. दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच आपूर्ति से संबंधित जोखिमों को भी उन्होंने चिंता का विषय करार दिया. विदेश मंत्री ने मंगलवार को मास्को में एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक को संबोधित किया.

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संगठन की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की बुराइयों से निपटने के लिए की गयी थी लेकिन बीते वर्षों में ये खतरे और गंभीर हो गये हैं. उन्होंने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसे किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता और इस मामले में कोई लीपापोती नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवादी हमलों के जवाब में अपने लोगों की रक्षा करने के अधिकार का इस्तेमाल किया है.

आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार

उन्होंने कहा हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों से निपटने के लिए की गई थी. बीते वर्षों में ये खतरे और भी गंभीर हो गए हैं. यह आवश्यक है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता प्रदर्शित करे. इसमें कोई औचित्य नहीं हो सकता, कोई अनदेखी नहीं हो सकती, और कोई लीपापोती नहीं हो सकती. जैसा कि भारत ने सिद्ध किया है, हमें आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और हम इसका प्रयोग करेंगे. डा. जयशंकर ने एससीओ की कार्यप्रणाली में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि संगठन निरंतर विकसित हो रहा है और भारत इसके सुधार-उन्मुख एजेंडे का पुरज़ोर समर्थन करता है. उन्होंने कहा, हम सभी मानते हैं कि एससीओ को समकालीन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना होगा. यह नई सोच और नए सहयोगों में परिलक्षित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने वाले केंद्रों का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा, जैसे-जैसे संगठन अधिक विविध होता जा रहा है, एससीओ को और अधिक लचीला और अनुकूलनशील होना होगा. इस उद्देश्य से, अंग्रेजी को एससीओ की आधिकारिक भाषा बनाने के लंबे समय से विलंबित निर्णय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

पीएमएफबीआई से किसानों को राहत

फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा, नुकसान की होगी भरपाई

नई दिल्ली, 18 नवंबर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में अब जंगली जानवरों और धान जलभराव के कारण फसल के होने वाले नुकसान को भी शामिल कर लिया गया है. इससे संबंधित नई प्रक्रियाएं खरीफ 2026 के सत्र से लागू होंगी.

यह जानकारी मंगलवार को यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गयी. नए नियम के अनुसार अगर कोई जानवर किसी किसान की बीमित फसल को नुकसान पहुंचाता है तो उसे बीमे की रकम मिल सकेगी. फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान को जंगली जानवर के फसल को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो सहित दर्ज करनी होगी. इसमें कहा गया है कि जंगली जानवरों से हुए फसल के नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी में पांचवें ऐड-ऑन कवर के रूप में मान्यता दी गई है. राज्यों को ऐसे प्रभावित इलाकों की पहचान करने और नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों की सूची जारी करने को कहा गया है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मंत्रालय का कहना है कि यह कदम लंबे समय से राज्यों की मांगों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य अचानक होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देना है. इसी के साथ धान के जलभराव से होने वाले नुकसान को भी %स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में दोबारा शामिल कर लिया गया है. वर्ष 2018 में इस जोखिम को हटाए जाने के बाद किसानों को बीमा सुरक्षा को लेकर समस्या आ रही थी.

जलभराव के चलते तटीय और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान के किसानों को अक्सर जलभराव से भारी नुकसान उठाना पड़ता है. गौरतलब है कि देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरन व बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण फसल के नुकसान का सामना करते रहे हैं. खेती करने वाले किसानों को अधिक आती है. ऐसे नुकसान बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो जाता था. दूसरी और तटीय एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान के किसानों को वर्षा और नदी-नालों के उफान से होने वाले जलभराव के कारण समान रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता रहा है.

अमेरिका-भारत साझेदारी पर प्रस्ताव पेश

वाशिंगटन/नई दिल्ली, 18 नवंबर. अमेरिकी संसद में सबसे लंबे समय तक सदस्य एमी बेरा और जो विल्सन ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया है.

अमेरिका और भारत के बीच दीर्घकालिक साझेदारी के रणनीतिक महत्व, स्थिरता और साझा लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की पुष्टि की गई है. इस प्रस्ताव को मजबूत द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है जिसमें सिडनी कामलागर-डोव, रिच मैककॉर्मिक, डेबोरा रॉस, रॉब विटमैन, सुहास सुब्रमण्यम और जे ओबरनोल्टे सहित 24 मूल सह-प्रायोजक शामिल हैं. यह प्रस्ताव विश्व के दो

सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, आतंकवाद-रोधी, शिक्षा एवं ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दशकों से बढ़ते सहयोग पर बल देता है. यह क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका का भी उल्लेख करता है.

अमेरिकी सांसदों ने इस बात पर बल दिया कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्थन पार्टी लाइन एवं राष्ट्रपति बदलने के बावजूद निरंतर रहा है. प्रस्ताव में कहा गया है, तीन दशकों से अधिक समय से, अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रम्प और बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है तथा क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक शासन एवं साझा वैश्विक प्राथमिकताओं के लिए इसके महत्व की पहचान की है.

एनजीटी के खाली पदों को भरने की गुहार, वकील पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के खाली पदों को भरने के लिए अधिकरण की बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि एनजीटी की प्रमुख और क्षेत्रीय पीठों में रिक्तियां को अगर जल्द न भरा गया तो इसकी कार्यप्रणाली के ही ठप होने का जोखिम हो जायेगा. एनजीटी की प्रधान पीठ की बार एसोसिएशन ने कहा कि न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या न्यूनतम दस-दस होनी चाहिए.

बांग्लादेशी 79 चालक दल को पकड़ा

- भारतीय तटरक्षक बल ने जलक्षेत्र में की कार्रवाई
- अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप

नई दिल्ली, 18 नवंबर. भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में बांग्लादेशी 79 चालक दल के सदस्यों को पकड़ा गया है.

आईसीजी के जहाजों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भारतीय जलक्षेत्र के भीतर काम करते हुए पाया गया.

यह अभियान पश्चिम बंगाल पुलिस और भारतीय तटरक्षक बल के बीच निर्बाध समन्वय और भारत के समुद्री हितों की रक्षा, अवैध मछली पकड़ने को रोकने और राष्ट्रीय जलक्षेत्र में काम करने वाले भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईसीजी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. भारतीय तटरक्षक बल समुद्री कानूनों को लागू करने और राष्ट्रीय समुद्री संपत्तियों की रक्षा के लिए निरंतर सतही और हवाई निगरानी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में निरंतर निगरानी बनाए रखता है.

गाजा में युद्धविराम के कड़े प्रावधानों का आग्रह

अम्मान, 18 नवंबर. जॉर्डन के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री अयमान सफादी और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने सोमवार को निर्धारित मतदान से पहले गजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय ने बताया कि मंत्रियों ने फोन पर हुई बातचीत में गजा में युद्धविराम को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने युद्धविराम को बनाए रखने के प्रयासों की भी समीक्षा की तथा मानवीय सहायता की तत्काल और पर्याप्त आपूर्ति सहित इसकी शर्तों का पूर्ण पालन करने का आह्वान किया.

नीतीश ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का किया निरीक्षण

पटना, 18 नवम्बर.बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण लिया.

नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है. निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों, नवनिर्वाचित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में पहुंचने वाले आगंतुकों के बैठने की

व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य उपलब्ध करायी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री जय कुमार चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सरावगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत अधिकारी उपस्थित थे.

तनाव में कमी लाने के लिए शीर्ष विदेशी अधिकारी को चीन भेजा

टोक्यो/बीजिंग. जापान ने चीन से बढ़ते द्विपक्षीय तनाव के बीच अपने विदेश मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी को चीन भेजा है जिससे तनाव को कम किया जा सके. यह कदम टोक्यो और बीजिंग के बीच राजनीतिक मतभेद के बाद उठाया गया है जिसके बाद दोनों एशियाई शक्तियों के बीच संक्षिप्त सैन्य एवं कूटनीतिक टकराव शुरू हो गई थी. जापानी मीडिया ने सोमवार को कहा कि जापानी विदेश मंत्रालय के एशियाई एवं महासागरीय मामलों के ब्यूरो के महानिदेशक मासाकी कनाई के चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के प्रमुख लियू जिनसोंग से मिलने की उम्मीद है.

सऊदी अरब को एफ-35 की बिक्री को मंजूरी देंगे : ट्रम्प

वाशिंगटन, 18 नवंबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मंगलवार को व्हाइट हाउस आएंगे तो वह सऊदी अरब को एफ-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी देंगे.

यह सात वर्षों में क्राउन प्रिंस की पहली अमेरिका यात्रा है. सीएनएन ने बताया कि श्री ट्रम्प अमेरिका-सऊदी संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वे क्राउन प्रिंस से अब्राहम समझौते में शामिल होने का भी आग्रह कर रहे हैं. उन्नत युद्धक विमानों की बिक्री की दिशा में आगे बढ़ने संबंधी सवाल

पर पत्रकारों के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हम ऐसा करेंगे. ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, हम एफ-35 बेचेंगे और सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा सहयोगी हैं. क्राउन प्रिंस के स्वागत के लिए सैन्य बैंड, तोपों की सलामी और घोड़ों के साथ स्वागत समारोह तथा ब्लैक-टाई डिनर का आयोजन भी सूची में शामिल है.

एसआईआर में सुरक्षा उपायों की रक्षा

खरगे व राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक

नई दिल्ली, 18 नवंबर. कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ऐसे समय पर कर रहा है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास डगमगाया हुआ है.

आयोग को अपने आचरण से साबित करना पड़ेगा कि वह सत्ताधारी दल के इशारे पर काम नहीं कर रहा है. कांग्रेस ने खरगे तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में मंगलवार को यहां इंदिरा भवन में उन 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्षों, प्रभारी महासचिवों, प्रदेश महासचिवों तथा अन्य नेताओं की बैठक बुलाई है जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान शुरू किया है. कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की किसी भी प्रक्रिया से वह संवैधानिक संस्थानों के लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों की रक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में शुद्धता चाहिए और पार्टी इसमें स्पष्टता के लिए प्रतिबद्ध है. लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही डगमगाया है.

ऐसे माहौल में चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह जनता का विश्वास हासिल कर यह साबित करे कि वह भाजपा के इशारे पर काम नहीं कर रहा है. उसे अपनी संवैधानिक शपथ और लोगों के प्रति निष्ठा जताते हुए अपने आचरण से दिखाना होगा कि वह सत्तारूढ़ दल के लिए काम नहीं कर रहा है. खरगे ने कहा हमारा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा वोट चोरी के लिए एसआईआर प्रक्रिया को हथियार बनाने का प्रयास कर रही है और यदि आयोग आँखें मूंद लेता है, तो यह नाकामी सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहेगी और उसकी यह चुप्पी की सांठगांठ बन जाएगी. उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता, बीएलओ और जिला, शहर, ब्लॉक अध्यक्ष लगातार सतर्क रहेंगे. हम वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने के हर प्रयास का पर्दाफाश करेंगे.

एक नजर में

पीएम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर

नई दिल्ली, 19 नवंबर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पीएम मोदी बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर जाएंगे. वह सुबह 10:30 बजे भगवान सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और उनके जीवन एवं शिक्षाओं के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का एक सेट जारी करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर जाएंगे. इस कार्यक्रम के दौरान वह 18,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाली पीएम-किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे . इससे पूरे देश के लगभग नौ करोड़ किसान लाभान्वित होंगे .तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारक मंच द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सतत एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है.

योगी ने मोदी के आगमन के तैयारियों की समीक्षा की

अयोध्या 18 नवम्बर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राममंदिर ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन की तैयारियों की समीक्षा की. श्री योगी ने श्री मोदी के आगमन की तिथि तय होने के बाद आज

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं जिला प्रशासन की तैयारियों को देखा और श्रीराम मंदिर परिसर में उच्चस्तरीय बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया और तैयारियों की बिन्दुवार समीक्षा की. बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र, राममंदिर प्रबंधन कार्य देख रहे गोपाल राव, जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, सूचना निदेशक विशाल सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक आर के स्वर्णकार, एडीजी सुजीत पांडेय, कमिश्नर राजेश कुमार आईजी प्रवीण कुमार उपस्थित थे.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

नई दिल्ली, 18 नवंबर. उच्चतम न्यायालय ने झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की जाँच से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से सवाल किया कि एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए क्यों किया जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य विधानसभा में कथित अवैध भर्तियों की सीबीआई जाँच का निर्देश दिया गया था. उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2024 में उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी.

भारत शेख हसीना को नहीं सौपेगा

नई दिल्ली, 18 नवंबर. बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया के राजनीतिक हलकों में दो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत उन्हें बंगलादेश को प्रत्यर्पित करेगा और भविष्य में बंगलादेश के साथ आगे क्या होगा, जो पहले से ही राजनीतिक व आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

बंगलादेश सरकार की ओर से हसीना के प्रत्यर्पण के आह्वान के जवाब में भारत ने इस मांग को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है और केवल इतना कहा है कि उसने हसीना के संबंध में बंगलादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के सुनाए गये फैसले पर ध्यान दिया है। इस तरह से बंगलादेश को भारत सरकार का संदेश स्पष्ट प्रतीत होता

है आप अपनी इच्छानुसार कोई भी मांग रख सकते हैं, लेकिन भारत कोई फैसला अपने तरीके से ही लेगा. विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव एवं बंगलादेश में भारतीय उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने बताया कि भारत ने बंगलादेश को पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि में एक छूट खंड शामिल है जो राजनीतिक या राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णयों का सामना कर रहे व्यक्तियों के प्रत्यर्पण पर रोक लगाता है.

मनोहर पर्रिकर-रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की शोध अध्येता पटनायक ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, अगर हम प्रत्यर्पण के मुद्दे पर बंगलादेश-भारत के दो बयानों को पढ़ें, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक-दूसरे से अलग बात कर रहे हैं. भारत किसी भी कदम पर विचार करने से पहले बंगलादेश में निर्वाचित सरकार के सत्ता में आने का इंतजार करेगा, हालांकि नियमित व्यापार और लोगों के बीच संपर्क अप्रभावित रहेंगे. गौरतलब है देश में उथल-पुथल या युद्ध से भागकर आए राष्ट्राध्यक्षों और उनके परिवारों को शरण देने का भारत का लंबा इतिहास रहा है.

मित्र शक्ति अभ्यास : सैनिकों ने रण कौशल में की जोर आजमाइश

नई दिल्ली 18 नवंबर. भारत और श्रीलंका के बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति-2025 में मंगलवार को विभिन्न सत्रों में दोनों पक्षों के सैनिकों ने रण कौशल की विधाओं में जोर आजमाइश की.

संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों टुकड़ियों के सैनिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और धैर्य, चपलता तथा समग्र युद्ध तैयारी का प्रदर्शन किया. अभ्यास में 170 सैनिकों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं. श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से गजबा रेजिमेंट के 135 सैनिक कर रहे हैं. भारतीय वायु सेना के 20 और श्रीलंकाई वायु सेना के 10 सैनिक भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं. कृत्रिम रूप से निर्मित क्षेत्रों में युद्ध पर एक व्यापक व्याख्यान भी आयोजित किया गया. इस सत्र में टोही अभियानों के लिए ड्रोन, त्वरित प्रेरण के लिए हल्के विशेषज्ञ और सभी क्षेत्रों में काम करने वाले वाहनों और खोजी अभियान के लिए रोबोट के उपयोग का प्रदर्शन किया गया. इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) पर एक विस्तृत व्याख्यान और प्रस्तुति में मार्ग-समाशोधन अभ्यास, आईईडी का पता लगाने के बाद की कार्रवाई, चार्ज की तैयारी और रेंडर सेफ प्रक्रियाओं को शामिल किया.

आज का इतिहास

1824 - रुस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बाढ़ से दस हजार लोगों की मौत।
1895 - फ्रेडरिक ई ब्लेसडेल ने पेंसिल का पेटेंट कराया।
1917 - इंदिरा गांधी का जन्म। वह भारत की चौथी प्रधानमंत्री थीं।
1928 - दारा सिंह, विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिन्दी फ़िल्मों के अभिनेता का जन्म।
1933 - यूरोपीय देश स्पेन में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला।
1951 - अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1952 - स्पेन यूनेस्को का सदस्य बना।

राहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमआईएस के प्रस्तावों को दी स्वीकृति

9,700 करोड़ के प्रस्तावों से किसानों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, 18 नवंबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) एवं बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के प्रस्तावों को आज स्वीकृति प्रदान की है.

इन स्वीकृत प्रस्तावों का उपज मूल्य 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ये निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी किसान-कल्याण के संकल्प के अनुरूप किसानों को आय-सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. केंद्रीय मंत्री शिवराज

सिंह चौहान द्वारा इन दोनों राज्यों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई महत्वपूर्ण बैठक में दी राज्यवार स्वीकृतियों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों के लिए मूंगफली खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई हैं, जिसके तहत स्वीकृत पात्र मात्रा 37,273 मीट्रिक टन हैं, जबकि अनुमानित उत्पादन 1,49,090 है. मंजूर प्रस्ताव का मूल्य 270.71 करोड़ रु. हैं. आंध्र प्रदेश के किसानों को भी 97,887 प्याज खरीद की स्वीकृति एमआईएस में देकर शिवराज सिंह ने राहत दी है. इसका मूल्य 24.47 करोड़ रु. है. बैठक में बताया गया कि राज्य ने रायतु सेवा केंद्रों पर आधार-बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है. स्वीकृति से किसानों को उपज बिक्री का मजबूत भरोसा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने राज्यों से खरीद व्यवस्था चाक-चौबंद रखने को कहा, ताकि कहीं-कोई गड़बड़ी नहीं हों, उपज खरीदी का पूरा लाभकिसानों को मिलें. शिवराज सिंह के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि खरीद केंद्रों पर आधार-सक्षम डिवाइस उपलब्ध हों, साथ ही किसान पंजीकरण व भुगतान के माध्यम से हो.

शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक का किया बहिष्कार

मुंबई, 18 नवंबर. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को छोड़कर उनकी पार्टी के सभी मंत्रियों ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया और सरकारी धन के कथित अनुचित वितरण पर कड़ी नाराजगी जताई.

शिवसेना (शिंदे गुट) के ज्यादातर मंत्री कैबिनेट बैठक के निर्धारित समय के दौरान राज्य सचिवालय में मौजूद थे और अपनी शिकायतें रखने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अलग से मिले. इस चर्चा का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. इस साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में संकटग्रस्त किसानों के लिए राहत उपायों पर

महत्वपूर्ण चर्चा और संभावित घोषणाएँ होने की उम्मीद थी. शिंदे गुट के मंत्रियों के बहिष्कार ने हालांकि एजेंडे को फीका कर दिया. अपने नेता एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भी मंत्रियों के बैठक से गायब रहने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आने के साथ कैबिनेट स्तर पर इस तरह की खुली कलह ने राज्य में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है.